



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

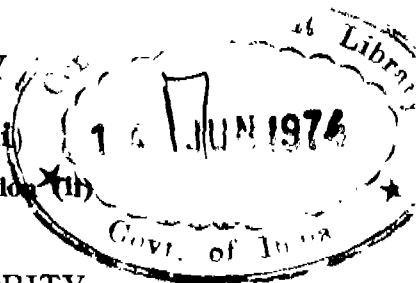
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

राष्ट्रिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



नं० 220]

नई दिल्ली, बुध्स्वतिवार, मई 16 1974/वैशाख 26, 1896

No. 220]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 1974/VAISAKHA 26, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DELIMITATION COMMISSION, INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May 1974

S.O. 293(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972), an Order made by the Delimitation Commission under section 8 of the said Act in respect of the State of Madhya Pradesh is hereby published:—

ORDER No. 15

In pursuance of section 8 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972), we hereby determine, on the basis of the latest census figures and having regard to the provisions of articles 81, 170, 330 and 332 of the Constitution, the number of seats in the House of the People to be allocated to the State of Madhya Pradesh as forty (40) of which five (5) seats shall be reserved for the Scheduled Castes and

eight (8) seats for the Scheduled Tribes and the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the State as three hundred and twenty (320) of which forty-two (42) seats shall be reserved for the Scheduled Castes and sixty-four (64) seats for the Scheduled Tribes.

J. L. KAPUR, Chairman.

TARUN KUMAR BASU, Member.

T. SWAMINATHAN, Member.

[No. 282/74(2)]

By order,

P. I. JACOB, Secy.

भारत परिसीमन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 1974

का० आ० 293 (अ).—परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के बारे में किया गया आदेश एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश सं० 15

परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 8 के अनुसरण में, हम, नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तथा संविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330 तथा 332 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य को लोक सभा में आबंटित किए जाने वाले स्थानों की संख्या चालीस (40) जिनमें से पांच (5) स्थान अनुसूचित जातियों के लिए तथा आठ (8) स्थान अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित होंगे तथा इस राज्य की विधान सभा के लिए समनुदेशित किए जाने वाले स्थानों की कुल संख्या तीन सौ बीस (320) जिनमें से बयालीस (42) स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और चौंसठ (64) स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे, एतद्वारा अवधारित करते हैं ।

जे० एल० कपूर, अध्यक्ष ।

तारुन कुमार बासु, सदस्य ।

ति० स्वामीनाथन, सदस्य ।

[सं० 282 / 74 (2)]

आदेश से

पी० आई० जेकर, सचिव ।